



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसारण

EXTRAORDINARY

भाग II—कांड 3—उप-कांड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, यंगलबार, भवन्दर 24, 1970/ग्राहायण 3, 1892

No. 423] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 1970/AGRAHAYANA 3, 1892

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकालन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE ORDER

New Delhi, the 24th November 1970

S.O. 3800/184/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of the opinion that the Keshav Mills Co. Ltd., Petlad, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to Public Interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorizes the Gujarat State Textile Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking namely, the Keshav Mills Co. Ltd., Petlad, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) The Authorised Controller shall comply with all direction issued from time to time by the Central Government;
- (ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order;
- (iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier if it considers necessary to do so.

2. This order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 9(4) Lie. Pol./69.]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

(1869)

श्रौद्धोगिक विकास तथा जातिसंरक्षण व्यापार मंज़ाल्य

प्रादेश

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1970

का० आ० 3800—18ए—प्राई० आ० आ० ए०/70.—यहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि केशव मिल्स कं० लि०, पेटलाड नामक एक श्रौद्धोगिक उपकरण का, जिसके सम्बन्ध में श्रौद्धोगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की गई, प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है;

अतः, अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य व स्त्र निगम (जिसे एतद्वोपरात्त प्राधिकृत नियंत्रक कहा जायेगा) को केशव मिल्स कं० लि०, पेटलाड नामक उपरोक्त सम्पूर्ण उपकरण का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्रतिकृत करती है, प्रथातः—

- (1) प्राधिकृत नियंत्रक, के नद्रीय सरकार द्वारा समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा;
- (2) प्राधिकृत नियंत्रक इस अधिसूचित प्रादेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये कार्यभार सम्पादित करेगा;
- (3) केन्द्रीय सरकार, यदि प्रावश्यक समझेगा, तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियकित को रद्द कर सकती है।

2. यह प्रादेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेगा।

[सं० फ० ९(४) लाई० पालिसी/६९]
के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव।